



“टेक - मेक – डिस्पोज” मॉडल

चर्चा में क्यों ?

- ❖ 'Reduce-Reuse-Recycle' मॉडल की बढ़ती आवश्यकता के साथ, भारत ने G-20 अध्यक्ष के रूप में संसाधन दक्षता को अपनाने और एक चक्रीय अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने पर ध्यान केंद्रित किया है।

प्रमुख बिंदु

- ❖ 'ग्रहीय चुनौतियों से निपटने में सामूहिक प्रयासों में संसाधन दक्षता और चक्रीय अर्थव्यवस्था प्रमुख समाधान के रूप में उभरी है'।
- ❖ संसाधन दक्षता और चक्रीय अर्थव्यवस्था शक्तिशाली रणनीतियाँ हैं जो प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भरता को प्रभावी ढंग से कम कर सकती हैं, अपशिष्ट को कम कर सकती हैं और टिकाऊ डिजाइन प्रथाओं को प्रोत्साहित कर सकती हैं।
- ❖ सतत विकास सुनिश्चित करने और सतत विकास लक्ष्यों को साकार करने के सामूहिक वैश्विक प्रयास में, संसाधन उपयोग को आर्थिक विकास से अलग करना महत्वपूर्ण होगा।
- ❖ 'टेक-मेक-डिस्पोज' से 'रिड्यूस-रीयूज-रीसाइक्लिंग' मॉडल पर स्विच करने की आवश्यकता को पहचानते हुए, भारत ने G-20 फोरम में विचार-विमर्श के लिए तीन मुख्य विषयों में से एक के रूप में 'संसाधन दक्षता और सर्कुलर इकोनॉमी' को प्राथमिकता दी है।
- ❖ भारत ने G-20 अध्यक्षता के दौरान चक्रीय अर्थव्यवस्था के लिए चार प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को अपनाया है:
 - इस्पात क्षेत्र में चक्रीयता।

- विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व (EPR)।
- सर्कुलर बायोइकोनॉमी और उद्योग के नेतृत्व वाली संसाधन दक्षता।
- सर्कुलर इकोनॉमी उद्योग गठबंधन की स्थापना।

चक्रीय इस्पात क्षेत्र की ओर बढ़ना

- ❖ अधिकांश G-20 सदस्य देश शुद्ध शून्य महत्वाकांक्षाओं के लिए प्रतिबद्ध हैं और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए काम कर रहे हैं।
- ❖ पर्यावरणीय रूप से जिम्मेदार तरीके से बढ़ती संसाधन खपत को सुनिश्चित करने के लिए, मौजूदा रीसाइक्लिंग दरों को 15%-25% तक बढ़ाने की भी आवश्यकता है।
- ❖ बुनियादी ढांचे के विकास में इस्पात की महत्वपूर्ण भूमिका के कारण इसका कुशल उपयोग महत्वपूर्ण है। स्टील की माँग विशेष रूप से भारत जैसी बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में बढ़ने की ओर अग्रसर है।
- ❖ विश्व स्तर पर, ऊर्जा क्षेत्र के उत्सर्जन का लगभग 7% लोहा और इस्पात, उत्पादन के लिए जिम्मेदार है।
- ❖ इस्पात क्षेत्र के उत्सर्जन से निपटने के लिए चक्रीय इस्पात क्षेत्र की ओर परिवर्तन एक महत्वपूर्ण रणनीति है।
- ❖ 'स्टील सेक्टर में सर्कुलर इकोनॉमी' पर ज्ञान के आदान-प्रदान के लिए प्रेसीडेंसी दस्तावेज़ इस्पात उद्योग के लिए शुद्ध शून्य मार्ग, संसाधन उपयोग को कम करने और अपव्यय को कम करने का एक संभावित खाका है।
- ❖ भारत की G-20 अध्यक्षता के तहत, संपूर्ण मूल्य श्रृंखला में सर्कुलरिटी को एकीकृत करने में EPR ढांचे के महत्व पर जोर दिया गया है। चूंकि विभिन्न देशों ने अलग-अलग EPR मॉडल लागू किए हैं, इसलिए G-20 सदस्य देशों को चक्रीय अर्थव्यवस्था में परिवर्तन हेतु तेजी लाने की आवश्यकता है।

पुनर्चक्रण, एक जैव अर्थव्यवस्था और जैव ईंधन

- ❖ EPR का प्रभावी कार्यान्वयन रीसाइक्लिंग बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देने और एक सुव्यवस्थित अपशिष्ट संग्रह प्रणाली स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

- ❖ केंद्रीकृत EPR पोर्टल पर 20,000 से अधिक पंजीकृत उत्पादकों, आयातकों और ब्रांड मालिकों (PIBO) तथा 1,900 से अधिक प्लास्टिक अपशिष्ट प्रोसेसर के साथ, भारत EPR के लिए सबसे बड़े ढांचे में से एक है।
- ❖ पंजीकृत PIBO का संयुक्त EPR दायित्व 3.07 मिलियन टन से अधिक है। भारत ने ई-कचरा और बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन के लिए व्यापक नियम भी अधिसूचित किए हैं।
- ❖ 1970 के बाद से G-20 सदस्य देशों में जैविक संसाधनों की खपत 2.5 गुना बढ़ गई है। नगरपालिका तथा औद्योगिक अपशिष्ट और कृषि अवशेष जैसे जैव अपशिष्ट एक वैश्विक मुद्दा बन गए हैं।

भारत द्वारा उठाये गये कदम

- ❖ भारत सरकार, जैव ईंधन को अपनाने की दिशा में काम कर रही है।
- प्रधानमंत्री जी-वन (जैव ईंधन – वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण) योजना-**
- ❖ यह दूसरी पीढ़ी (2G) इथेनॉल परियोजनाओं को स्थापित करने के लिए एकीकृत जैव-इथेनॉल परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
- ❖ 2G बायोएथेनॉल तकनीक फसल अवशेषों और नगरपालिका ठोस अपशिष्ट जैसे अपशिष्ट फीडस्टॉक से बायोएथेनॉल का उत्पादन करती है जिसका अन्यथा कोई मूल्य नहीं होता।
- ❖ भारत ने कोयला जलाने वाले थर्मल पावर प्लांटों के लिए कोयले के साथ बायोमास छर्कों के 5% मिश्रण का उपयोग करना भी अनिवार्य कर दिया है।

गोबर्धन योजना

- ❖ टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने और प्रदूषण को कम करने के लिए मवेशियों के गोबर और अन्य जैविक कचरे को खाद, बायोगैस और जैव ईंधन में परिवर्तित करने के लिए भारत सरकार द्वारा गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो-एग्रो रिसोर्सेज (GOBAR) धन योजना शुरू की गई थी।
- ❖ 500 से अधिक कार्यात्मक बायोगैस संयंत्रों के साथ, इस योजना ने ग्रामीण आजीविका बनाने में भी मदद की है और बेहतर स्वच्छता सुनिश्चित की है।

सतत योजना

- ❖ वैकल्पिक हरित परिवहन ईंधन के रूप में कंप्रेसड बायोगैस (CBG) के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 2018 में शुरू की गई सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन (SATAT) योजना ने CBG के उत्पादन, भंडारण और वितरण के लिए बुनियादी ढांचे के विकास में तेजी लाकर बायोएनर्जी क्षेत्र को सहायता प्रदान की है।

उद्योग गठबंधन

- ❖ चूंकि उद्योग संसाधन दक्षता और चक्रीय अर्थव्यवस्था प्रथाओं को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण हैं, इसलिए भारत ने इन क्षेत्रों में एक उद्योग गठबंधन की कल्पना की है। गठबंधन का लक्ष्य उन्नत तकनीकी सहयोग प्राप्त करना, सभी क्षेत्रों में उन्नत क्षमताओं का निर्माण करना, जोखिम रहित वित्त जुटाना और एक सक्रिय निजी क्षेत्र की भागीदारी को सुविधाजनक बनाना होगा।

